भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 431
(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए)

फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याएं

431. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री इटैला राजेंदर:
श्रीमती डी. के. अरुणा:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को होने वाली समस्याओं के मुद्दों पर कुछ रिपोर्टों में यौन शोषण, अवैध प्रतिबंध, भेदभाव, नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग, वेतन असमानता और कुछ मामलों में तो अमानवीय कार्य स्थितियों की भयावह कहानियां सामने आई हैं और यह पाया गया है कि उद्योग कुछ पुरुष निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं के चंगुल में है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा फिल्म उद्योग में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): सरकार ने महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने और ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" (एसएच अधिनियम) अधिनियमित किया है। यह अधिनियम फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिलाओं सहित सभी महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनकी उम्र, रोजगार की स्थिति या काम का प्रकार

कुछ भी हो, चाहे वे सार्वजनिक या निजी, या संगठित, असंगठित, औपचारिक या अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हों। यह सार्वजनिक और निजी दोनों कार्यस्थलों में नियोक्ताओं पर यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है। नियोक्ताओं को 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में एक आंतरिक समिति (आईसी) गठित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त सरकार को प्रत्येक जिले में एक स्थानीय समिति (एलसी) गठित करने का अधिकार है, जो दस से कम कर्मचारियों वाले संगठनों से प्राप्त शिकायतों या जहां नियोक्ता के विरुद्ध शिकायत हो, पर कार्रवाई करेगी।